an>

Title: Need to make proper arrangement for procurement of agriculture produce at Minimum Support Price particularly in Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सरकार द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं लेकिन किसानों द्वारा उत्पादन की जाने वाली कृषि जिन्सों का सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था नियमित एवं सही ढंग से नहीं किए जाने की वजह से कृषकों को अपनी जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दरों पर बाजार में बेचना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था के अभाव में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्ष 2013-14 में नैफेड द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीद तो की गई थी लेकिन राजफैड द्वारा 9.62 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को आज तक नहीं किया गया है। उसके बाद आज तक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन पर कृषि जिन्सों की सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा किसानों को ओलावृष्टि एवं सूखे का भुगतान भी आज तक नहीं किया गया है। काश्तकार को बिचौलियों से बचाने एवं समर्थन मूल्य का पूरा लाभ देने के लिए बाजार मूल्य एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की अन्तर राशि का भुगतान सरकार द्वारा किसान के खाते में सीधा किया जाना चाहिए ताकि किसान को समर्थन मूल्य का सीधा लाभ मिल सके व सरकार द्वारा यातायात, परिवहन, माल गोदाम, भाड़ा, कटौती व बारदाना आदि का जो सरकारी खर्च होता है, उससे भी बचा जा सकता है।